

कालेजियम का कवच और न्यायपालिका की साख पर उठते सवाल

जिस देश की अदालतों में करीब साढ़े चार करोड़ मुकदमे फैसले का इंतजार कर रहे हैं लाखों लोगों को जीवन भर अदालतों की चौखट पर सिर पटकने के बाद भी न्याय नहीं मिल पाता है वहीं के देवता अकूत संदेदा जमा कर ऐसी व्यवस्था बनाए बैठे है कि उनके कारनामों की सहज प्रशुचिता भरी जांच भी उन्हीं के कुलदेवताओं की मर्जी पर टिकी है? क्या हमारी न्याय व्यवस्था विश्वास के संकट के दौर में नहीं है? न्यायालय के एक न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास के एक कमरे से कथित रूप से बेहिसाब नगदी की बरामदगी ने देश के जनमानस को न्यायिक तंत्र में पैर जमा रहे भ्रष्टाचार पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक जांच समिति गठित की है। वहीं पारदर्शिता सुनिश्चित करने और गलत सूचनाओं को दूर करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक की है। इस रिपोर्ट ने निष्कर्ष दिया है कि पूरे मामले की गहन जांच की आवश्यकता है। ऐसा जरूरी भी था क्योंकि उच्च न्यायपालिका की ईमानदारी और विश्वसनीयता दांव पर है। हालांकि, न्यायाधीश ने दावा किया है कि उनके या परिवार के किसी सदस्य द्वारा स्टोर रूम में कभी कोई नकदी नहीं रखी गई थी। कोई भी व्यक्ति जिसके घर दफ्तर या लाकर से बिना हिसाब किताब का आय से अधिक धन या सम्पत्ति मिलता तो वो वह इसी तरह अपना बचाव करता है और यहाँ तो मामला चालीस साल से वकालत और न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत व्यक्ति से जुड़ा है तो उन्हें अपने बचाव के लिए ऐसा ही तमाम बातें बनानी होगी। इस बयान ने भी कई सवालों को जन्म दिया है। सवाल उठया जा रहा है कि कड़ी सुरक्षा में रहने वाले सरकारी आवास में क्या बिना जानकारी के पैसा रखा जा सकता है? तो क्या किन्हीं आवासीय कर्मचारियों या बाहरी लोगों ने ऐसा कृत्य किया? यदि यह वास्तव में जज को फंसाने की सजिश थी, तो उसमें कौन

लोग शामिल थे? निश्चित रूप से ऐसे सवालों का जवाब मिलने में विलंब से अविश्वास की धुंध और गहरी होगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाए गए ऐतिहासिक %न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन% में यह निर्दिष्ट किया गया था कि किसी न्यायाधीश द्वारा ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं होनी चाहिए, जो उनके उच्च पद और उस पद के प्रति सार्वजनिक सम्मान के अनुरूप न हो।% निस्संदेह, न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम करने वाले किसी भी विवाद की गहरी जांच होनी चाहिए। साथ यह भी जरूरी है कि जांच निर्धारित समय सीमा में अनिवार्य रूप से पूरी हो। वास्तव में सत्य, न्याय और न्यायिक जवाबदेही के हित में ऐसे मामलों में न्याय पालिका के लिए बनी साख पर भी जबरदस्त कुठाराघात किया है।

सवाल उठता है कि 14 मार्च को हुई आग लगने की घटना के साथ ही जज साहब के आवास के एक कमरे में बोरों में रखे करोड़ों के नोट धधक रहे थे तब इस बात के जाहिर होने के बाद भी जिम्मेदार व्यवस्था और न्यायपालिका के सर्वेसर्वा माननीय सीजेआई महोदय ने इस मामले की जांच या भ्रष्टाचार के खुलासा के लिए पर्याप्त सक्रियता दिखाई या नहीं दिखाई और मामले पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की गई। यदि ऐसा नहीं है तो 14 मार्च की इतनी बड़ी घटना की सात दिन तक मीडिया से छिपा कर क्यों रखा गया। फायर विभाग के कर्मचारियों द्वारा आग बुझाने के दौरान बड़ी मात्रा में अधजले नोटों की आग बुझाने की विडियो बना ली गई और अधिकारियों को जानकारी दी गई अधिकारियों ने पुलिस और प्रशासन को जानकारी दी न्यायपालिका के जिम्मेदार तंत्र को भी सूचित कर दिया गया लेकिन मामले पर पांच छह दिन तक अदालत और जज साहब से जुड़ा मामला होने का दबाव बना रहा लेकिन अंततः भांडा फूट गया जब कोलेजियम द्वारा संबंधित जज साहब का दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरण कर मामले को दबाने का नाकाम कोशिश की गई। सवाल उठे न्यूज चैनल पर सनसनी बनी सोशल मीडिया पर मीम बने तो एक बार फिर एक फायर सर्विस अधिकारी से

बड़ी मात्रा में नोटों के बोरों की बरामदगी से इंकार कराया गया यहां तक कि जज साहब के ट्रांसफर को भी इस घटना से इत्र सामान्य तौर पर रूटीन ट्रांसफर बता कर पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई। सवाल उठता है कि क्या एक सिपाही को दो सौ रुपये की रिश्तत लेने पर किसी अदालत के जिम्मेदार पदों पर आसिन माननीय को अपनी निष्पक्ष छवि बनाते हुए मामले का पता चलते ही संबंधित जज साहब के आवास की जामा तलाशी नहीं करानी चाहिए थी जब एक कमरे में कथित करीब पंद्रह करोड़ की नकदी स्वाहा होने का अनुमान है तो बाकी कमरों की आलमारी और लाकरों में कितना ज्वैलरी बेनामी सम्पत्ति मिल सकती थी। यदि एक बारगी जज महोदय के स्पष्टीकरण बयान पर ही भरोसा किया जाए कि नकदी उनकी जानकारी में नहीं थी फंसाने का षडयंत्र हो सकता है क्या पता बाकी कमरों में भी किसी ने उन्हें फसाने के लिए अकूत संपत्ति रख दी होगे? ऐसा लगता है कि इस मामले में सिर्फ लीपापोती की जा रही है जांच के लिए अब इडी आयकर विभाग तमाम भ्रष्टाचार निवारण तंत्र के अधिष्ठानों को, क्यों सक्रिय नहीं किया गया? क्या न्यायाधीश पद का असली फायदा यही है कि कालेजियम कवच बन जाता है? आग लगने की घटना के ठीक तेरह दिन बाद पुलिस कथित जांच के लिए सिर्फ स्टोर रूम तक पहुंच पाती है? ऐसी जांच से कोई खास पारदर्शी निष्पक्ष निष्कर्ष सामने आने की उम्मीद करना भी सिर्फ तसल्ली देने जैसा है। इस मौजूदा व्यवस्था को कालेजियम की व्यवस्थाओं को क्या इस भ्रष्टाचार के संरक्षण के लिए ही प्रभावी बनाया गया है?

बहरहाल, शीर्ष अदालत ने विवादों में घिरे न्यायाधीश के प्रति कथित सख्त रहैया अपनाते हुए उन्हें न्यायिक कामकाज से अलग रखने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक विमर्श में उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की चर्चा भी रही। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घटनाक्रम से जुड़े कॉल्स सुरक्षित रखने को कहा है।

अदालत ने पिछले छह माह के कॉल रिकॉर्ड भी पुलिस से मांगे हैं। वहीं दूसरी ओर शीर्ष अदालत ने पुलिस द्वारा रिकॉर्ड वीडियो, तस्वीरें व शुरुआती जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक विमर्श में ला दी है। निश्चित रूप से न्याय की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से बेदाग होने की उम्मीद का सवालों के घेर में आना एक गंभीर मुद्दा है। इस घटनाक्रम से न्याय व्यवस्था पर जो बदनुमा छींटे आए हैं, उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से साफ करना जरूरी है।उम्मीद करना चाहिए है कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित जांच समिति सच को सामने लाने में पारदर्शी व निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ की शुचिता साख अक्षुण्ण रखने के लिये यह बहुत जरूरी भी है। निस्संदेह, न्यायपालिका का लक्ष्य सिर्फ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना ही नहीं है बल्कि सार्वजनिक जीवन में निष्पक्षता, ईमानदारी और विश्वसनीयता के मूल्यों के आदर्शों को स्थापित और पोषण करना चाहिए । लेकिन न्यायपालिका में पूर्ण सम्मान के साथ बहुत विनम्रता के साथ बिना किसी पूर्वाग्रह के लिखना पड़ता है कि मौजूदा मामले में जिस तरह की सुस्त लचीलापन लिए प्रक्रिया अपनाई गई है वह स्वयं मे ही कई सवाल खड़े करती है यह एक लोकतांत्रिक देश की स्वतंत्र अस्तित्व वाली न्यायपालिका के लिए आत्मावलोकन की गंभीर जरूरत और उसमे पनपे कथित कदाचार व भ्रष्टाचार के खिलाफ तत्काल सटीक और प्रभावी धिरे न्यायाधीश के प्रति कथित सख्त रहैया अपनाते हुए उन्हें न्यायिक कामकाज से अलग रखने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक विमर्श में उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की चर्चा भी रही। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घटनाक्रम से जुड़े कॉल्स सुरक्षित रखने को कहा है।

मनोज कुमार अग्रवाल

अब राणा सांगा को लेकर जंग का आगाज

हमारा मुल्क बिना जंग के रह नहीं सकता । हम बमुश्किल औरंगजेब से फ़ारिग हुए थे कि गुरु रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को मैदाने जंग में ला खड़ा किया। राणा सांगा की ओर से अब ये लड़ाई करणी सेना लड़ रही है और सुमन की ओर से अखिलेश यादव की यादवी सेना। हम आम जनता मुकदर्शक बने इस जंग को देख रहे हैं। हम न इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं और न हमारी इस जंग का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी है। हाँ हमारी दिलचस्पी इस बात में जरूर है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की उत्तरदायी सरकार कैसे एक निर्वाचित संसद को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाती । राणा सांगा के बारे में जानने से पहले आप रामजी लाल सुमन के बारे में जान लीजिये । कोई 48 साल का संसदीय अनुभव रखने वाले रामजीलाल सुमन चंद्रशेखर से लेकर मुलायम सिंह जैसे कद्दावर नेताओं के भरोसेमंद और विश्वसनीय साथ ही रहे हैं। 25 जुलाई 1950 को हाथरस जनपद के बढेदाई गांव में जन्मे रामजीलाल सुमन की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई. उनकी माध्यमिक शिक्षा हाथरस में और उच्च शिक्षा आगरा कॉलेज में हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन पहली बार 1977 में लोकसभा पहुंचे थे। यानि हमारे सुमन जी हमारे प्रधानमंत्री जी की उम्र के हैं और उनसे पुराने सांसद हैं। उन्हें इतिहास का ज्ञान भी कम नहीं है। आपकों बता दें कि रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में कहा था, अगर मुसलमानों को बाबर का वंशज कहा जाता है, तो हिंदू गद्दार राणा सांगा के वंशज होने चाहिए। हम बाबर की आलोचना करते हैं, लेकिन राणा सांगा की आलोचना क्यों नहीं करते ? सुमन ने सवाल किया था, जंगे ऐलान नहीं। कोई राजपूत,कोई हिन्दू हदय सम्राट सुमन कि सवाल का शास्त्रोक्त जबाब देकर मामला शांत कर सकता था ,लेकिन दुभाग्य की जबाब देते लिए एपढ़े-लिखे लोगों का टोटा है। सपा अधःयक्ष अखिलेश यादव ने भी सुमन के इस बयान का समर्थन किया है। इसके बाद विवाद शुरू हो गया है। सुमन ने यह भी कहा था कि आखिर बाबर को भारत कौन लाया। यह राणा

सांगा ही थे जिन्होने बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था।अब गवाही कि लिए न इब्राहिम लोदी आ सकते हैं और न राणा सांगा। बाबर को भी समन नहीं किया जा सकता। भरोसा इतिहास की किताबों पर ही करना होगा।

रामजीलाल सुमन के बयान के बाद करणी सेना भड़क गयी। ये सेना राणा सांगा के समय में थी या नहीं ,मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि ये वो सेना है जो एक फिल्म का विरोध करने के लिए सड़कों पर पहली बार उतरी थी । ये सेना भारतीय सेना की कोई ब्रिगेड है या नहीं ये भी मैं नहीं जानता। हमारे देश में भारतीय सेना के अलावा भी अनेक सेनाएं हैं। इन सेनाओं पर कोई लगाम नहीं लगाता। एक जमाने में बिहार में ऐसी निजी सेनाओं का बहुत बोलबाला था, लेकिन बाद में सबकी बोलती बंद होगयी। उत्तरप्रदेश में करणी सेना की बोलती बंद नहीं हुई क्योंकि सूबे की सरकार ने इस सेना को तोड़फोड़ करने के लिए अधिमान्य कर रखा है अन्यथा किसी भी निजी सेना की क्या मजाल कि वो 75 साल के एक प्रतिष्ठित नेता के घर को घेर कर वहां तोड़फोड़ करे और पुलिस को भी घायल कर दे ?

लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को है। करणी सेना को भी , लेकिन विरोध प्रदर्शन के तरीके भी हैं । सुमन ने यदि कुछ गलत कहा है तो उनकी लालपुत राज्य सभा में की जाये। क्या करनी सेना की और से एक भी राजपूत राज्य सभा में नहीं है जो खड़े होकर सुमन के बयान का विरोध कर सके ? करणी सेना को राजपूती अस्मिता की इतनी ही फ़िक्र है तो उसे पुलिस थाने जाना चाहिए अदालत जाना चाहिए ,लेकिन इतना ठठकर्म कौन करे। सड़क पर आकर जंग लड़ना ज्यादा आसान है। कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में इसी तर्ज पर शिवसेना [एकनाथ शिंदे समूह] ने भी लड़ाई लड़ी। कानून हाथ में लेने में उतनी मशक्कत नहीं करना पड़ती जितनी की कानूनी रूप से जंग लड़ने में करना पड़ती है। शिंदे समर्थकों को कुणाल कि मुंह से 'गद्दार 'शब्द बुरा लगा लेकिन सुमन ने यह भी कहा था कि आखिर बाबर को भारत कौन लाया। यह राणा



घर तोड़फोड़ करने नहीं गया। ठीक इसी तरह रामजीलाल सुमन के मुंह से गद्दार सशब्द सुनकर करनी सेना की आत्मा घायल हो गयी।

चूँकि हमारा इस जंग से सीधे कोई सरोकार नहीं है इसलिए हम तमाशबीन की हैसियत में हैं। तमाशबीन या तो तालियां बजाते हैं या फिर सीटियाँ। तमाशा समाप्त होने पर पान चबाते या गुटका खाते हुए अपने घरों को लौट जाते हैं। राणा सांगा बनाम रामनीलाल सुमन की जंग में भी यही सब होता दिखाई दे रहा है। सत्ता पोषित हिंसा के हम सब मूक दर्शक हैं। हमारा क़ानून वहां तोड़फोड़ करे और पुलिस को भी घायल कर दे ? लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को है। करणी सेना को भी , लेकिन विरोध प्रदर्शन के तरीके भी हैं । सुमन ने यदि कुछ गलत कहा है तो उनकी लालपुत राज्य सभा में की जाये। क्या करनी सेना की और से एक भी राजपूत राज्य सभा में नहीं है जो खड़े होकर सुमन के बयान का विरोध कर सके ? करणी सेना को राजपूती अस्मिता की इतनी ही फ़िक्र है तो उसे पुलिस थाने जाना चाहिए अदालत जाना चाहिए ,लेकिन इतना ठठकर्म कौन करे। सड़क पर आकर जंग लड़ना ज्यादा आसान है। कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में इसी तर्ज पर शिवसेना [एकनाथ शिंदे समूह] ने भी लड़ाई लड़ी। कानून हाथ में लेने में उतनी मशक्कत नहीं करना पड़ती जितनी की कानूनी रूप से जंग लड़ने में करना पड़ती है। शिंदे समर्थकों को कुणाल कि मुंह से 'गद्दार 'शब्द बुरा लगा लेकिन सुमन ने यह भी कहा था कि आखिर बाबर को भारत कौन लाया। यह राणा

सांगा ही थे जिन्होने बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था।अब गवाही कि लिए न इब्राहिम लोदी आ सकते हैं और न राणा सांगा। बाबर को भी समन नहीं किया जा सकता। भरोसा इतिहास की किताबों पर ही करना होगा।



हमारी भावनाएं छुईमुई हैं जो हाल कुम्हला जातीं हैं, आहत हो जातीं हैं। मजे की बात ये है कि आहत भावनाओं का कोई भेषजीय उपचार नहीं है । आहत भावनाएं केवल खून-खराबा और अराजकता पैदाकर अपना इलाज खुद करना चाहती हैं। रामजीलाल सुमन पर हमला कर, करनी सेना ने हिन्दू-मुसलमान नहीं बल्कि हिन्दू -बनाम हिन्दू संघर्ष को न्यौता दिया है । एक तरफ करणी सेना के हिन्दू हैं तो दूसरी तरफ वे हिन्दू हैं जो अनुसूचित जाति के कहे और माने जाते हैं। हमारी सरकार भी यही चाहती है कि लोग इसी तरह से अपनी धार्मिक,जातीय भावनाओं को आहत करते-करते रहें और लड़ते-लड़ाते रहें। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि इस तरह की गतिविधियों से हमारे विश्वगुरु बनने के अभियान में खलल पड़ता है।

काश कि इस तरह के विवादों में पीड़ित पक्ष के रूप में खुद औरंगजेब या राणा सांगा की आत्माएं प्रकट होकर जंग लड़तीं। मुमकिन है कि वे लड़ती ही नहीं क्योंकि वे दोनों तो अब एक ही आ-जा सकते हैं और हंगामा खड़ा कर वापस भी लौट सकते हैं।राणा सांगा को भी हमने उसी तरह नहीं देखा जिस तरह की औरंगजेब को नहीं देखा था। राणा की बहादुरी के किस्से हमने भी पढ़े हैं,सुने हैं लेकिन देखे नहीं हैं। सुमन ने भी नहीं देखे होंगे और करणी सेना ने भी। सबने जैसे औरंगजेब और उनकी और सुना होगा जैसे की दूसरे नायकों,खलनायकों, अधिनायकों के बारे में पढ़ा और सुना जाता है।

अतीत के किरदारों को लेकर हमारी भावनाएं आग की तरह कलंग भड़कती हैं ,इसके बारे में शोध होना चाहिए।

राकेश अवल

भारतीय नवसंवत्सर - युगधर्म का उद्घोष बने

भारत में चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि (युगादि तिथि) से हिंदू नव वर्ष की अर्थात विक्रम संवत की शुरुआत होती है। इस वर्ष यह पावन दिन (संवत् 2082 का प्रथम दिवस) भारत में सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत ग्रेगरियन कैलेंडर जिसे हम अंग्रेजी/ईसाई कैलेंडर भी कहते हैं के अनुसार 30 मार्च,2025 को आ रहा है। शासन स्तर पर अंग्रेजी कैलेंडर के प्रचलन में होने के बावजूद भारत अपनी धार्मिक, सामाजिक तथा अन्य सांस्कृतिक परंपराओं के निर्वहन के लिए भारतीय कैलेंडर को सदियों से महत्व देता रहा है।भारत की ही तरह कुछ और देश भी है जो पूरी तरह ग्रेगेरियन कैलेंडर को नहीं मानते हैं तथा पूर्व में भी कई राज्यों के हाइकोर्ट तथा अधीनस्थ अदालतों के जजों का आचरण प्रतिकूल मिलने के मामलों की काफी तादाद है। समझ सकते हैं कि अन्याय के विरुद्ध उम्मीद की अंतिम किरण लेकर न्याय की चौखट पर दस्तक देता है। यदि यह भरोसा भी टूट जाएगा तो देश के सामने अराजकता और बदअमनी के माहौल की हालात बन सकते हैं । निस्संदेह, न्याय व्यवस्था का सवालों के घेर में आना एक गंभीर मुद्दा है। इस घटनाक्रम से न्याय व्यवस्था पर जो बदनुमा छींटे आए हैं, उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से साफ करना जरूरी है।उम्मीद करना चाहिए है कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित जांच समिति सच को सामने लाने में पारदर्शी व निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ की शुचिता साख अक्षुण्ण रखने के लिये यह बहुत जरूरी भी है। निस्संदेह, न्यायपालिका का लक्ष्य सिर्फ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना ही नहीं है बल्कि सार्वजनिक जीवन में निष्पक्षता, ईमानदारी और विश्वसनीयता के मूल्यों के आदर्शों को स्थापित और पोषण करना चाहिए । लेकिन न्यायपालिका में पूर्ण सम्मान के साथ बहुत विनम्रता के साथ बिना किसी पूर्वाग्रह के लिखना पड़ता है कि मौजूदा मामले में जिस तरह की सुस्त लचीलापन लिए प्रक्रिया अपनाई गई है वह स्वयं मे ही कई सवाल खड़े करती है यह एक लोकतांत्रिक देश की स्वतंत्र अस्तित्व वाली न्यायपालिका के लिए आत्मावलोकन की गंभीर जरूरत और उसमे पनपे कथित कदाचार व भ्रष्टाचार के खिलाफ तत्काल सटीक और प्रभावी धिरे न्यायाधीश के प्रति कथित सख्त रहैया अपनाते हुए उन्हें न्यायिक कामकाज से अलग रखने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक विमर्श में उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की चर्चा भी रही। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घटनाक्रम से जुड़े कॉल्स सुरक्षित रखने को कहा है।

अदालत ने पिछले छह माह के कॉल रिकॉर्ड भी पुलिस से मांगे हैं। वहीं दूसरी ओर शीर्ष अदालत ने पुलिस द्वारा रिकॉर्ड वीडियो, तस्वीरें व शुरुआती जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक विमर्श में ला दी है। निश्चित रूप से न्याय की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से बेदाग होने की उम्मीद का सवालों के घेर में आना एक गंभीर मुद्दा है। इस घटनाक्रम से न्याय व्यवस्था पर जो बदनुमा छींटे आए हैं, उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से साफ करना जरूरी है।उम्मीद करना चाहिए है कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित जांच समिति सच को सामने लाने में पारदर्शी व निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ की शुचिता साख अक्षुण्ण रखने के लिये यह बहुत जरूरी भी है। निस्संदेह, न्यायपालिका का लक्ष्य सिर्फ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना ही नहीं है बल्कि सार्वजनिक जीवन में निष्पक्षता, ईमानदारी और विश्वसनीयता के मूल्यों के आदर्शों को स्थापित और पोषण करना चाहिए । लेकिन न्यायपालिका में पूर्ण सम्मान के साथ बहुत विनम्रता के साथ बिना किसी पूर्वाग्रह के लिखना पड़ता है कि मौजूदा मामले में जिस तरह की सुस्त लचीलापन लिए प्रक्रिया अपनाई गई है वह स्वयं मे ही कई सवाल खड़े करती है यह एक लोकतांत्रिक देश की स्वतंत्र अस्तित्व वाली न्यायपालिका के लिए आत्मावलोकन की गंभीर जरूरत और उसमे पनपे कथित कदाचार व भ्रष्टाचार के खिलाफ तत्काल सटीक और प्रभावी धिरे न्यायाधीश के प्रति कथित सख्त रहैया अपनाते हुए उन्हें न्यायिक कामकाज से अलग रखने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक विमर्श में उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की चर्चा भी रही। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घटनाक्रम से जुड़े कॉल्स सुरक्षित रखने को कहा है।

मनोज कुमार अग्रवाल

राकेश अवल

भारत में चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि (युगादि तिथि) से हिंदू नव वर्ष की अर्थात विक्रम संवत की शुरुआत होती है। इस वर्ष यह पावन दिन (संवत् 2082 का प्रथम दिवस) भारत में सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत ग्रेगरियन कैलेंडर जिसे हम अंग्रेजी/ईसाई कैलेंडर भी कहते हैं के अनुसार 30 मार्च,2025 को आ रहा है। शासन स्तर पर अंग्रेजी कैलेंडर के प्रचलन में होने के बावजूद भारत अपनी धार्मिक, सामाजिक तथा अन्य सांस्कृतिक परंपराओं के निर्वहन के लिए भारतीय कैलेंडर को सदियों से महत्व देता रहा है।भारत की ही तरह कुछ और देश भी है जो पूरी तरह ग्रेगेरियन कैलेंडर को नहीं मानते हैं तथा पूर्व में भी कई राज्यों के हाइकोर्ट तथा अधीनस्थ अदालतों के जजों का आचरण प्रतिकूल मिलने के मामलों की काफी तादाद है। समझ सकते हैं कि अन्याय के विरुद्ध उम्मीद की अंतिम किरण लेकर न्याय की चौखट पर दस्तक देता है। यदि यह भरोसा भी टूट जाएगा तो देश के सामने अराजकता और बदअमनी के माहौल की हालात बन सकते हैं । निस्संदेह, न्याय व्यवस्था का सवालों के घेर में आना एक गंभीर मुद्दा है। इस घटनाक्रम से न्याय व्यवस्था पर जो बदनुमा छींटे आए हैं, उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से साफ करना जरूरी है।उम्मीद करना चाहिए है कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित जांच समिति सच को सामने लाने में पारदर्शी व निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ की शुचिता साख अक्षुण्ण रखने के लिये यह बहुत जरूरी भी है। निस्संदेह, न्यायपालिका का लक्ष्य सिर्फ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना ही नहीं है बल्कि सार्वजनिक जीवन में निष्पक्षता, ईमानदारी और विश्वसनीयता के मूल्यों के आदर्शों को स्थापित और पोषण करना चाहिए । लेकिन न्यायपालिका में पूर्ण सम्मान के साथ बहुत विनम्रता के साथ बिना किसी पूर्वाग्रह के लिखना पड़ता है कि मौजूदा मामले में जिस तरह की सुस्त लचीलापन लिए प्रक्रिया अपनाई गई है वह स्वयं मे ही कई सवाल खड़े करती है यह एक लोकतांत्रिक देश की स्वतंत्र अस्तित्व वाली न्यायपालिका के लिए आत्मावलोकन की गंभीर जरूरत और उसमे पनपे कथित कदाचार व भ्रष्टाचार के खिलाफ तत्काल सटीक और प्रभावी धिरे न्यायाधीश के प्रति कथित सख्त रहैया अपनाते हुए उन्हें न्यायिक कामकाज से अलग रखने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक विमर्श में उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की चर्चा भी रही। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घटनाक्रम से जुड़े कॉल्स सुरक्षित रखने को कहा है।

अदालत ने पिछले छह माह के कॉल रिकॉर्ड भी पुलिस से मांगे हैं। वहीं दूसरी ओर शीर्ष अदालत ने पुलिस द्वारा रिकॉर्ड वीडियो, तस्वीरें व शुरुआती जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक विमर्श में ला दी है। निश्चित रूप से न्याय की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से बेदाग होने की उम्मीद का सवालों के घेर में आना एक गंभीर मुद्दा है। इस घटनाक्रम से न्याय व्यवस्था पर जो बदनुमा छींटे आए हैं, उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से साफ करना जरूरी है।उम्मीद करना चाहिए है कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित जांच समिति सच को सामने लाने में पारदर्शी व निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ की शुचिता साख अक्षुण्ण रखने के लिये यह बहुत जरूरी भी है। निस्संदेह, न्यायपालिका का लक्ष्य सिर्फ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना ही नहीं है बल्कि सार्वजनिक जीवन में निष्पक्षता, ईमानदारी और विश्वसनीयता के मूल्यों के आदर्शों को स्थापित और पोषण करना चाहिए । लेकिन न्यायपालिका में पूर्ण सम्मान के साथ बहुत विनम्रता के साथ बिना किसी पूर्वाग्रह के लिखना पड़ता है कि मौजूदा मामले में जिस तरह की सुस्त लचीलापन लिए प्रक्रिया अपनाई गई है वह स्वयं मे ही कई सवाल खड़े करती है यह एक लोकतांत्रिक देश की स्वतंत्र अस्तित्व वाली न्यायपालिका के लिए आत्मावलोकन की गंभीर जरूरत और उसमे पनपे कथित कदाचार व भ्रष्टाचार के खिलाफ तत्काल सटीक और प्रभावी धिरे न्यायाधीश के प्रति कथित सख्त रहैया अपनाते हुए उन्हें न्यायिक कामकाज से अलग रखने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक विमर्श में उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की चर्चा भी रही। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घटनाक्रम से जुड़े कॉल्स सुरक्षित रखने को कहा है।

संपादकीय

भारतीय नवसंवत्सर - युगधर्म का उद्घोष बने

भारत में चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि (युगादि तिथि) से हिंदू नव वर्ष की अर्थात विक्रम संवत की शुरुआत होती है। इस वर्ष यह पावन दिन (संवत् 2082 का प्रथम दिवस) भारत में सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत ग्रेगरियन कैलेंडर जिसे हम अंग्रेजी/ईसाई कैलेंडर भी कहते हैं के अनुसार 30 मार्च,2025 को आ रहा है। शासन स्तर पर अंग्रेजी कैलेंडर के प्रचलन में होने के बावजूद भारत अपनी धार्मिक, सामाजिक तथा अन्य सांस्कृतिक परंपराओं के निर्वहन के लिए भारतीय कैलेंडर को सदियों से महत्व देता रहा है।भारत की ही तरह कुछ और देश भी है जो पूरी तरह ग्रेगेरियन कैलेंडर को नहीं मानते हैं तथा पूर्व में भी कई राज्यों के हाइकोर्ट तथा अधीनस्थ अदालतों के जजों का आचरण प्रतिकूल मिलने के मामलों की काफी तादाद है। समझ सकते हैं कि अन्याय के विरुद्ध उम्मीद की अंतिम किरण लेकर न्याय की चौखट पर दस्तक देता है। यदि यह भरोसा भी टूट जाएगा तो देश के सामने अराजकता और बदअमनी के माहौल की हालात बन सकते हैं । निस्संदेह, न्याय व्यवस्था का सवालों के घेर में आना एक गंभीर मुद्दा है। इस घटनाक्रम से न्याय व्यवस्था पर जो बदनुमा छींटे आए हैं, उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से साफ करना जरूरी है।उम्मीद करना चाहिए है कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित जांच समिति सच को सामने लाने में पारदर्शी व निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ की शुचिता साख अक्षुण्ण रखने के लिये यह बहुत जरूरी भी है। निस्संदेह, न्यायपालिका का लक्ष्य सिर्फ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना ही नहीं है बल्कि सार्वजनिक जीवन में निष्पक्षता, ईमानदारी और विश्वसनीयता के मूल्यों के आदर्शों को स्थापित और पोषण करना चाहिए । लेकिन न्यायपालिका में पूर्ण सम्मान के साथ बहुत विनम्रता के साथ बिना किसी पूर्वाग्रह के लिखना पड़ता है कि मौजूदा मामले में जिस तरह की सुस्त लचीलापन लिए प्रक्रिया अपनाई गई है वह स्वयं मे ही कई सवाल खड़े करती है यह एक लोकतांत्रिक देश की स्वतंत्र अस्तित्व वाली न्यायपालिका के लिए आत्मावलोकन की गंभीर जरूरत और उसमे पनपे कथित कदाचार व भ्रष्टाचार के खिलाफ तत्काल सटीक और प्रभावी धिरे न्यायाधीश के प्रति कथित सख्त रहैया अपनाते हुए उन्हें न्यायिक कामकाज से अलग रखने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक विमर्श में उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की चर्चा भी रही। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घटनाक्रम से जुड़े कॉल्स सुरक्षित रखने को कहा है।

दिवस के रूप में स्वीकार है, और अधिकांश भारतीय भी उसी रूप में इसका पूरे हर्ष और उल्लास से स्वागत करते हैं जैसे महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आदि गुड़ी पड़वा के रूप में।आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आदि के रूप में तथा राजस्थान थापना के रूप में। वहीं सिंधी समाज इस तिथि को चेती चंद के रूप में तथा कश्मीरी पंडितों द्वारा इस तिथि को नवरेह के रूप में मनाया जाता है। एक विचार आता है कि अंग्रेजी कैलेंडर तथा (विक्रम संवत्सर) को नववर्ष के प्रथम दिवस के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त है। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल से ही इस कलेंडर को सरकारी व निजी संस्थानों द्वारा व्यवहार में लाया जा रहा है, तथा इसकी एक जनवरी को नए साल की शुरुआती दिन के रूप में कैलेंडर को भी महत्व देते हैं जैसे ईरान, अफगानिस्तान (हिजरी कैलेंडर), इथियोपिया (इथियोपियन कैलेंडर), नेपाल (विक्रम संवत्),सऊदी अरब (इस्लामिक तथा ग्रेगरियन कैलेंडर) तथा चीन (चीनी चंद्र कैलेंडर), भारत (विक्रम संवत्), इजरायल (हिब्रू कैलेंडर) आदि। हिन्दुओं द्वारा नव संवत्सर के प्रथम दिवस को नव वर्ष की शुरुआत के रूप में मान्यता देने के पीछे कई ठोस सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक तथा अध्यात्मिक कारण है।ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी(ब्रह्मपुराण) तथा कालगणना (समय-गणना) प्रारंभ की थी। इसी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम तथा धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था ,इसी तिथि से समयुग आरंभ हुआ था, इसी तिथि से लचीलापन लिए प्रक्रिया अपनाई गई है वह स्वयं मे ही कई सवाल खड़े करती है यह एक लोकतांत्रिक देश की स्वतंत्र अस्तित्व वाली न्यायपालिका के लिए आत्मावलोकन की गंभीर जरूरत और उसमे पनपे कथित कदाचार व भ्रष्टाचार के खिलाफ तत्काल सटीक और प्रभावी धिरे न्यायाधीश के प्रति कथित सख्त रहैया अपनाते हुए उन्हें न्यायिक कामकाज से अलग रखने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक विमर्श में उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की चर्चा भी रही। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घटनाक्रम से जुड़े कॉल्स सुरक्षित रखने को कहा है।

अदालत ने पिछले छह माह के कॉल रिकॉर्ड भी पुलिस से मांगे हैं। वहीं दूसरी ओर शीर्ष अदालत ने पुलिस द्वारा रिकॉर्ड वीडियो, तस्वीरें व शुरुआती जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक विमर्श में ला दी है। निश्चित रूप से न्याय की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से बेदाग होने की उम्मीद का सवालों के घेर में आना एक गंभीर मुद्दा है। इस घटनाक्रम से न्याय व्यवस्था पर जो बदनुमा छींटे आए हैं, उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से साफ करना जरूरी है।उम्मीद करना चाहिए है कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित जांच समिति सच को सामने लाने में पारदर्शी व निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ की शुचिता साख अक्षुण्ण रखने के लिये यह बहुत जरूरी भी है। निस्संदेह, न्यायपालिका का लक्ष्य सिर्फ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना ही नहीं है बल्कि सार्वजनिक जीवन में निष्पक्षता, ईमानदारी और विश्वसनीयता के मूल्यों के आदर्शों को स्थापित और पोषण करना चाहिए । लेकिन न्यायपालिका में पूर्ण सम्मान के साथ बहुत विनम्रता के साथ बिना किसी पूर्वाग्रह के लिखना पड़ता है कि मौजूदा मामले में जिस तरह की सुस्त लचीलापन लिए प्रक्रिया अपनाई गई है वह स्वयं मे ही कई सवाल खड़े करती है यह एक लोकतांत्रिक देश की स्वतंत्र अस्तित्व वाली न्यायपालिका के लिए आत्मावलोकन की गंभीर जरूरत और उसमे पनपे कथित कदाचार व भ्रष्टाचार के खिलाफ तत्काल सटीक और प्रभावी धिरे न्यायाधीश के प्रति कथित सख्त रहैया अपनाते हुए उन्हें न्यायिक कामकाज से अलग रखने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक विमर्श में उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की चर्चा भी रही। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घटनाक्रम से जुड़े कॉल्स सुरक्षित रखने को कहा है।

अदालत ने पिछले छह माह के कॉल रिकॉर्ड भी पुलिस से मांगे हैं। वहीं दूसरी ओर शीर्ष अदालत ने पुलिस द्वारा रिकॉर्ड वीडियो, तस्वीरें व शुरुआती जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक विमर्श में ला दी है। निश्चित रूप से न्याय की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से बेदाग होने की उम्मीद का सवालों के घेर में आना एक गंभीर मुद्दा है। इस घटनाक्रम से न्याय व्यवस्था पर जो बदनुमा छींटे आए हैं, उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से साफ करना जरूरी है।उम्मीद करना चाहिए है कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित जांच समिति सच को सामने लाने में पारदर्शी व निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ की शुचिता साख अक्षुण्ण रखने के लिये यह बहुत जरूरी भी है। निस्संदेह, न्यायपालिका का लक्ष्य सिर्फ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना ही नहीं है बल्कि सार्वजनिक जीवन में निष्पक्षता, ईमानदारी और विश्वसनीयता के मूल्यों के आदर्शों को स्थापित और पोषण करना चाहिए । लेकिन न्यायपालिका में पूर्ण सम्मान के साथ बहुत विनम्रता के साथ बिना किसी पूर्वाग्रह के लिखना पड़ता है कि मौजूदा मामले में जिस तरह की सुस्त लचीलापन लिए प्रक्रिया अपनाई गई है वह स्वयं मे ही कई सवाल खड़े करती है यह एक लोकतांत्रिक देश की स्वतंत्र अस्तित्व वाली न्यायपालिका के लिए आत्मावलोकन की गंभीर जरूरत और उसमे पनपे कथित कदाचार व भ्रष्टाचार के खिलाफ तत्काल सटीक और प्रभावी धिरे न्यायाधीश के प्रति कथित सख्त रहैया अपनाते हुए उन्हें न्यायिक कामकाज से अलग रखने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक विमर्श में उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की चर्चा भी रही। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घटनाक्रम से जुड़े कॉल्स सुरक्षित रखने को कहा है।

अदालत ने पिछले छह माह के कॉल रिकॉर्ड भी पुलिस से मांगे हैं। वहीं दूसरी ओर शीर्ष अदालत ने पुलिस द्वारा रिकॉर्ड वीडियो, तस्वीरें व शुरुआती जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक विमर्श में ला दी है। निश्चित रूप से न्याय की कुर्सी पर बैठे

कारवाई की। अब जल्द ही इस ग्रीन बेल्ट का सौंदर्यीकरण होगा, जिससे जानकीपुरम विस्तार में हरियाली बढ़ेगी और अपार्टमेंट्स की सुंदरता निखरेगी। स्थानीय निवासियों ने इस फैसले पर प्रसन्नता जाहिर की है और लखनऊ विकास प्राधिकरण का आधार व्यक्त किया है।

संक्षिप्त ख़बरें

केशव नगर मदरसा स्काई विल्ड्रेन एकेडमी के 2 बच्चों का नवोदय विद्यालय में हुआ चयन।

मनकापुर गोण्डा। क्षेत्र के केशव नगर ग्रांट पश्चिमी कैदराबाद में मदरसा स्काई चिल्ड्रेन एकेडमी विद्यालय कक्षा पांच के दो छात्रों दिव्यांश वर्मा पुत्र दिनेश कुमार वर्मा केशव नगर ग्रांट पश्चिमी और युवराज वर्मा पुत्र विजय प्रताप वर्मा मनकापुर चौबेपुर इन दोनों छात्रों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छह में हुआ हैं। दो बच्चों का चयन होने पर विद्यालय में खुशी का माहौल हैं।बृहस्पतिवार को मुख्य अतिथि अरुण प्रताप सिंह उर्फ डब्लम सिंह ने दोनों छात्रों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, और कहा कि नवोदय मे कक्षा छह में अपने मेहनत से स्थान पक्का करके अपने गुरुजनों, अभिभावकों व सभी मार्गदर्शकों का नाम रोशन किया है।विद्यालय के प्रबंधक जावेद खान , एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक के.के.यादव, अध्यापक अभय प्रताप मिश्रा ने भी इन दोनों छात्रों को सम्मानित किया। बच्चों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने अभिभावकों और गुरुजनों को दिया है। बच्चों की इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी की लहर है।

बलिया में कक्षा 1 के छात्र को शिक्षक ने बेरहमी से पीटा

बलिया (यूपी)। शिक्षा क्षेत्र रेवती से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। मामला कपोजित विद्यालय रेवती (वार्ड नंबर 8) है, जहां आइसक्रीम खरीदने गए कक्षा एक के छात्र को विद्यालय के शिक्षक ने बेरहमी से पीट दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला संवाददाता सैयद सेराज अहमद ने बताया कि शिक्षक की पिटाई से छात्र के हाथ और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। इससे छात्र न सिर्फ सदमे, बल्कि बहवास स्थिति में है। छात्र का एक वीडियो भी सामने आया है। वायरल वीडियो में छात्र डरा सहमा दिख रहा है। वह बता रहा है कि बर्फ खरीदने गया था, लौटा तो सर जी ने उसे डंडे से मारा। छात्र पीटने वाले सर का नाम भी बता रहा है। वायरल वीडियो में छात्र के शरीर पर छड़ी के चोट से बने निशान भी दिख रहा है। वहीं, वीडियो का संज्ञान बीएसए मनीष कुमार सिंह ने लिया है। बीएसए ने कहा है कि खण्ड शिक्षा अधिकारी को जांच सौंपी गई है। रिपोर्ट मिलते ही सम्बंधित शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

सैंती में हंडंपं मरम्मत में घोटाले का आरोप: बिना काम के निकाल लिए 82 हजार रुपए, एक दिन में 3 बार निकाली रकम

टडियावा/ हरदोई विकास खंड टडियावा



में हंडंपं मरम्मत के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। सैंती ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर बिना काम कराए ही लाखों रुपये निकाल लिए। इस मामले में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है।ग्राम पंचायत सैंती के निवासी मोनु गाजी ने डीएम को बताया कि गांव में पिछले 4 साल से कई इंडिया मार्का हंडंपं खराब पड़े हैं। गर्मी के मौसम में इससे पानी की गंभीर समस्या हो सकती है। नाजिर के घर के पास, महेंद्र और भयन्नु के घर के पास लगे हंडंपं पिछले 4 साल से काम नहीं कर रहे हैं। वहीं मंगल बाग बाजार में भी हंडंपं खराब है, जिससे राहगीरों को परेशानी होती है।

अजय झा ने बस स्टैंड का उक किया अपने नाम, 33 लाख 92 हजार रुपए की लगी उच्चतम बोली।



बहादुरगंज (किशनगंज)- नगर पंचायत बहादुरगंज के कार्यपालक पदाधिकारी अतिउर्हमान के कार्यालय बैरम में जहान अली मस्तान बस पड़ाव लिए आर पी चौक का डाक प्रक्रिया सम्पन्न हुआ। काफ़ी जद्दो जहद के बाद कुल 87 राउंड चले डाक प्रक्रिया में अजय झा ने सबसे ऊंची बोली 33 लाख 92 हजार रुपए लगाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बस स्टैंड का डाक अपने नाम कर लिया है, जबकि पिछले साल डाक की अधिकतम बोली 21 लाख 82 हजार 7 सौ रुपए थी। इस दौरान मुख्य रूप से इस निलामी में शामिल रहे नप कार्यपालक पदाधिकारी अतिउर रहमान,पार्षद बन्टी सिन्हा, वार्ड पार्षद आफताब आलम, शहबाज अनवर, प्रधान लेखापाल फुल कुमार इश्तेहार आलम सहित अन्य उपस्थित थे।

विद्यालय में बने स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब व बाउंड्री वॉल और भवन रिनोवेशन का लोकार्पण

स्वतंत्र प्रभात

सिद्धार्थनगर। महात्मा गौतम बुद्ध उत्तर माध्यमिक विद्यालय जोगिया में गुरुवार को एडसिल इंडिया लिमिटेड के तत्वाधान में एक हेल्थ कैंप का उद्घाटन और महात्मा गौतम बुद्ध उत्तर माध्यमिक विद्यालय जोगिया में स्थापित दो स्मार्ट क्लास तथा एक कंप्यूटर लैब ,साथ ही बाउंड्री वॉल और भवन रिनोवेशन का लोकार्पण मुख्य अतिथि गोविंद जायसवाल आईएसएस संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार तथा अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक एडसिल द्वारा लोकार्पण किया गया । विद्यालय में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पार्चन कर नमन किया गया तथा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ।प्रधानाचार्य बृजेश द्विवेदी द्वारा आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया ,छात्राओं द्वारा सभी अतिथियों को स्वयं का बनाया बुके भेंट किया। विद्यालय की प्रबंध समिति की अध्यक्ष कविता साहनी द्वारा मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रभु दयाल विद्यार्थी से जुड़ी यादों का मोमेंटो भेंट किया ।अतिथियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रभु दयाल विद्यार्थी



की समाधि स्थल पर माल्यार्पण कर पुष्पार्चन कर नमन किया। तत्पश्चात मुख्य पुष्पार्चन कर नमन किया गया तथा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ।प्रधानाचार्य बृजेश द्विवेदी द्वारा आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया ,छात्राओं द्वारा सभी अतिथियों को स्वयं का बनाया बुके भेंट किया। विद्यालय की प्रबंध समिति की अध्यक्ष कविता साहनी द्वारा मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रभु दयाल विद्यार्थी से जुड़ी यादों का मोमेंटो भेंट किया ।अतिथियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रभु दयाल विद्यार्थी

सिसोदिया डिटी जीएम नंदीश जी मैनेजर एम बो नदाफ , हेल्थ कैंप मैनेजर कुलदीप सिंह चौहान डॉक्टर शिवम डॉक्टर विशाल मिश्रा डॉक्टर साक्षी मिश्रा नर्सिंग स्टाफ लैब टेक्नीशियन रामसेवक साहनी ,उप प्रबंधक विशुनकुश साहनी विद्यालय प्रबंध समिति की अध्यक्ष कविता साहनी , प्रबंध समिति की कोषाध्यक्ष चमेली देवी,लक्ष्मी सिंह सोनाली देवी ,अरुण लाल श्रीवास्तव, अंगद प्रसाद,दिनेश धर द्विवेदी, दुर्गेश,राजन गोंड मुनीराम, शीतल मिश्रा गोपाल साहनी, रोहित साहनी,बब्बू साहनी, चन्देव यादव जिला प्रसाद, एडसिल के सीजीएम प्रदीप सिंह

बिहार के सरकारी डॉक्टरों की तीन दिवसीय हड़ताल ओपीडी सेवाएं ठप, मरीजों को भारी परेशानी

स्वतंत्र प्रभात

बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने गुरुवार से तीन दिन की हड़ताल शुरू कर दी है। इसके कारण त्रिवेणीगंज में बाहरी मरीजों के इलाज (ओपीडी) की सेवाएं ठप हो गई हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार उनके वेतन, सुर्खा और स्टाफ की कमी जैसी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। हड़ताल के कारण मरीजों को भारी परेशानी हो रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों के मरीजों को, जो सरकारी अस्पतालों पर निर्भर होते हैं। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ (भासा) ने बायोमेट्रिक हाजिरी, प्रशासनिक दबाव और कर्मचारियों की कमी जैसे मुद्दों का विरोध करते हुए हड़ताल बुलाई थी। हालाँकि, हड़ताल केवल ओपीडी सेवाओं तक ही सीमित रही, जबकि आपातकालीन और ट्रॉमा सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं। डॉ. उमेश कुमार ने कहा, सरकार हमारी मांगों पर चुप है,

कोचाधामन प्रखंड के गरगांव पंचायत में तेजी गति के साथ चल रहा है पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य, प्रत्येक दिन संबंध विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं कार्यस्थल पर

स्वतंत्र प्रभात

किशनगंज- जिला अंतर्गत कोचाधामन प्रखंड के ग्राम पंचायत गरगांव में लंबे समय बाद पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली। कागजी प्रक्रिया पूर्ण होने तत्पश्चात पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ है। वहीं आपको बता दें कि कार्यकारी एजेंसी भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। उक्त पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य जय मातादी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है जिसके संवेदक सुशांत कुमार हैं। वहीं पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानकों को लेकर भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता जहांगीर अहमद पहुंचे कार्यस्थल। उन्होंने आमजनो के साथ- साथ जनप्रतिनिधियों को आश्वासित किया कि गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों के साथ भवन का कार्य ससमय



जिससे हमें काम छोड़ने का फैसला करना पड़ा। हमने गुरुवार से तीन दिन की हड़ताल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और सामान्य रूप से चलती रहीं। डॉ. उमेश कुमार ने कहा, सरकार हमारी मांगों पर चुप है,

अस्पताल अधिकारी ने कहा, गरीब मरीज, खासकर जो गांवों से आते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि वे निजी अस्पतालों का खर्च नहीं उठा सकते। भासा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार 29 मार्च तक कोई ठोस समाधान नहीं निकालती है, तो वे आगे भी कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे।



पूरा किया जाएगा। उक्त पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य 3 करोड़ से अधिक की लागत से इसका निर्माण कार्य होना है पूर्ण।

गरगांव पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोश सज्जाद कैसर द्वारा लगातार कार्यस्थल पर पहुंचकर कार्य का जायजा

लिया जाता है ताकि बन रहें पंचायत सरकार भवन गुणवत्तापूर्ण सामग्री के साथ हो पूरा। पंचायत से संबंधित सभी कार्य पंचायत वासियों का पंचायत सरकार भवन में ही होगा पूरा। पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य को देखकर स्थानीय ग्रामीणों में खुशी का माहौल व्याप्त है।

कटेया के वैष्णव मठ पर मनाया गया हिन्दू वाहिनी का स्थापना दिवस : राजीव रंजन पाण्डेय

स्वतंत्र प्रभात

गोपालगंज (कटेया)- जिले के कटेया प्रखंड अन्तर्गत कटेया के प्राचीन वैष्णव मठ के पावन एवं पवित्र धरती पर हिन्दू वाहिनी का स्थापना दिवस प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन की अध्यक्षता में बहुत धूम धाम से मनाया गया आपको बता दें हिन्दू वाहिनी की मासिक बैठक साल के बारहों महीने में बड़ी सालिनता तथा व्यवहारिक रूप में की जाती हैं हिन्दु वाहिनी की मासिक बैठक संगठन के विस्तार के लिए की जाती हैं एक बात चित में हिन्दू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन पाण्डेय ने बताया कि यह हिन्दू वाहिनी एक ऐसा संगठन है जिसमें भारत माता कि आन बान शान को बचाये रखने के लिए बड़ी मधुरता और शालीनता के रूप में कार्य किया जाता हैं हिन्दू वाहिनी के पदाधिकारियों एवं समस्त सदस्यों के द्वारा जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए विशेष रूप से बैठक किया जाता हैं तथा किया जाता रहेगा पाण्डेय ने बताया कि हिन्दू वाहिनी में जुड़े हुए लोग अपने जीवन से संबंधित तथा अपने परिवार के लिए एक लेकिन जन के कार्यों में ज्यादा समय लगाते हैं उन्होंने बताया कि हिन्दू वाहिनी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा महीने में एक बार बैठक जरुरी रूप में की



जाती हैं हिन्दू वाहिनी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन पाण्डेय बताते हैं कि हिन्दू वाहिनी एक पारिवारिक संगठन के रूप में कार्य करता हैं इसमें जितने पदाधिकारी एवं सदस्य हैं सभी लोग मिल जुलकर अपनी स्तर पर कार्य करने के लिए उत्साहित रहते हैं जिससे कि समाज में लोगों के उपर एक सकारात्मक सोच उभर कर आवे सभी महीने में एक बार बैठक जरुरी रूप में की

शालीनता से अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन पाण्डेय, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश मिश्र, जिला प्रभारी नवल किशोर चौबे, प्रखंड अध्यक्ष अजीत चौबे, प्रखंड प्रभारी अनु दास जी महाराज, जिला मीडिया प्रभारी शैलेश कुमार तिवारी, एवं अन्य पदाधिकारी सदस्य तथा वैष्णव मठ के कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद पदाधिकारी एवं सदस्य बैठक में बड़ी

सिलापथार में केन्द्रीय महासती जयमती स्मृति दिवस 2025 पालन

स्वतंत्र प्रभात

पधेमाजी असम। सिलापथार शाखा नाट्य सम्मेलन, सिलापथार शाखा साहित्य सभा, सिलापथार आंचलिक ताई अहोम छत्र संस्था, सिलापथार क्षेत्रीय असम जातीयतावादी युवा छत्र परिषद और सिलापथार लेखक और महिला समाज ने आज सिलापथार पब्लिक हॉल में एक दिवसीय कार्यक्रम के साथ सिलापथार केन्द्रीय महासती जयमती स्मृति दिवस 2025 का आयोजन किया। सुबह सामूहिक सफाई, वृक्षारोपण, ध्वजारोहण और शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पण के बाद सिलापथार शहर में विशाल सांस्कृतिक जुलूस निकाला गया। दोपहर का सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायन और नृत्य के साथ शुरू हुआ। जिसमें सिलापथार क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आमंत्रित कलाकारों ने आई नाम, बिया नाम, मरान बिहू, बिहू नृत्य, जंग बिहू, देउरी, सोनवाल, मिर्चिग लोक नृत्य और आहूम लाओ तुंग खाम नृत्य प्रस्तुत किया। सेवानिवृत्त शिक्षक लखीनाथ बोड़ा द्वारा की मुनीराम, शीतल मिश्रा गोपाल साहनी, रोहित साहनी,बब्बू साहनी, चन्देव यादव जिला पंचायत सदस्य आदि लोग मौजूद रहे



बरगोहाई के अध्यक्षता में एक बैठक किया गया, बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में शिवसागर से निजरा हैडीकी ने भाग लिया

और,सती साधिनी की जयमती, मूला गवर और कनकलता के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला। उन्होंने अहोमों की वीरता और वृहत्तर असम के निर्माण में आहूम लोगों की योगदान के बारे में भी विस्तार से बताया। बैठक में धेमाजी जिला साहित्य सभा के अध्यक्ष बिनोद गोर्गोई, सिलापथार शाखा साहित्य समिति के अध्यक्ष विजय कोवर, शिक्षाविद् गकुल शैकिया, सामाजिक कार्यकर्ता दुलाल बरुआ, स्वागत समिति सलाहकार भूगेश ताये सहित भारी संख्या में लोगों शामिल हुए।

टैबलेट और स्मार्ट फोन विद्यार्थियों के लिए रोजगार सृजन के अनेक अवसरों को उपलब्ध कराने वाला साबित होगा : कुलपति प्रोफेसर कविता शाह

स्वतंत्र प्रभात

सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर कविता शाह ने कहा कि विद्यार्थी शिक्षण संस्थानों के ध्वजवाहक होते हैं। उनकी कौशल और दक्षता से शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ समाज की भी प्रगति होती है। प्रसन्नता का विषय है की छात्राएं भी अब हर क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य कर रही हैं। युवाओं की दक्षता और क्षमता विकसित भारत के परिकल्पना को साकार रूप देने में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं संचालित किये जा रहे हैं। तकनीकी सहयोग के लिए निशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण विद्यार्थियों के रोजगार सृजन के अनेक अवसरों को उपलब्ध कराने वाला साबित होगा। विश्वविद्यालय में बहुत से नवाचार हो रहे हैं। विद्यार्थी केंद्रित इन नवाचारों के माध्यम से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की पहचान राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बन सकेगी। जिससे यहां के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भविष्य में आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध होंगे। शिक्षण संस्थानों के साथ विद्यार्थियों के रागात्मक संबंध संस्थान के प्रगति के लिए आवश्यक होता है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय पुरातन छात्र



को इस हेतु अपने साथ जोड़ने के अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर सदर विधायक श्याम धनी राही ने कहा कि मुख्यमंत्री की चिंता में और केंद्र में युवा सर्वाधिक आगे हैं। इसलिए युवाओं पर केंद्रित अनेक कार्यक्रम और संसाधनों के माध्यम से सहयोग का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। टैबलेट एवं स्मार्ट वितरण का महा अभियान भी उसी का एक हिस्सा है। विद्यार्थी इसका सकारात्मक उपयोग करें निश्चित रूप से उनका भविष्य में मजबूत बनाने में आत्म निर्भर बनाने में विद्यार्थी केंद्रित इन नवाचारों के माध्यम से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की पहचान राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बन सकेगी। जिससे यहां के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भविष्य में आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध होंगे। शिक्षण संस्थानों के साथ विद्यार्थियों के रागात्मक संबंध संस्थान के प्रगति के लिए आवश्यक होता है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय पुरातन छात्र

से संबंधित कार्यों के लिए अनेक प्रकार के सहयोग प्राप्त हैं। विद्यार्थी के हाथ में यदि स्मार्टफोन है तो आज की तिथि में वह दुनिया की सारी जानकारी से अपने को संपन्न कर सकता है और बड़े-बड़े शिक्षण संस्थानों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अपना स्थान बना सकता है। कार्यक्रम में कुल सचिव डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह भी मंच पर उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर नीता यादव ने किया। संचालन डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह ने किया। कार्यक्रम में अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय एवं आइक्यूएसी के निदेशक प्रोफेसर सौरव श्रीवास्तव कल अनुशासक प्रोफेसर दीपक बाबू रसायन विज्ञान के आचार्य डॉक्टर बलिराम सहित शिक्षक कर्मचारी एवं छात्र -छात्राएं उपस्थित रहे। टैबलेट वितरण कार्यक्रम में 78 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

आप सबकी आवाज पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता डॉ0 तारा श्वेता आर्या के द्वारा इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन

● - इफ्तार दावत में दिखा भाईचारा, हिंदू मुस्लिम समाज के लोग हुए शामिल

स्वतंत्र प्रभात

किशनगंज- मंगलवार को आप सबकी आवाज पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने शहर के मदरसा अजुमन इस्तामिया में शहरवासियों के लिए इफ्तार दावत का आयोजन किया। इस मौके पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों ने बड़-चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजित पार्टी में शहर के कई बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुईं। डॉ. तारा श्वेता आर्या ने कहा कि इफ्तार दावत के आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में सौहार्द, भाईचारा और एकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि भारत की गंगा-जमुनी तहजीब



हमें हमेशा एकता और आपसी प्रेम का संदेश देती है। ऐसे आयोजनों से समाज में मिल-जुलकर रहने की परंपरा को और अधिक मजबूती मिलती है।

उन्होंने कहा कि इफ्तार पार्टी का मकसद सिर्फ रोजेदारों को भोजन कराना नहीं, बल्कि सभी समुदायों के लोगों को एक मंच पर लाना और उनके बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ाना भी था।कार्यक्रम में शामिल होने वालों ने भी इसे सकारात्मक पहल बताया। शहर के गणमान्य सौहार्द, भाईचारा और एकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि भारत की गंगा-जमुनी तहजीब

है। इफ्तार के दौरान लोग एक-दूसरे के साथ बैठे, संवाद किया और इस पवित्र माह की महत्ता को समझा। इस दौरान स्थानीय मौलवियों ने भी अपने विचार रखे और समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि रमजान का महीना केवल इबादत का नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और इंसानियत का भी महीना है। वहीं, हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन यह साबित करते हैं कि सभी धर्म नगरिकों का कहना था कि ऐसे आयोजनों से समाज में धार्मिक समरसता को बढ़ावा मिलता

विधवा महिला ने घर में घुस कर मारपीट का लगाया आरोप,एसपी से लगाई न्याय की गुहार

सिद्धार्थनगर। दुमरियागंज थाना क्षेत्र के धनोहरी गांव निवासी एक विधवा महिला ने घर में घुस कर मारपीट का आरोप लगाया है।पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर दुमरियागंज पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है। दुमरियागंज थाना क्षेत्र के धनोहरी गांव निवासी विधवा महिला मालती पत्नी स्व.कमल किशोर ने एसपी को दिए अपने शिकायती पत्र में बताया है कि 21 मार्च को शाम करीब सात बजे घर के भीतर मिट्टी का चूल्हा बना रही थी।इसी समय गांव के बृज व वासुदेव पुत्र राम लखन घर में घुसे और गाली गलौज करते हुए ईंट,पत्थर,व लात घूंसे से काफी मारा पीटा,शोर सुनकर बीच बचाव करने आई पतोहू को मार पीट कर घायल कर दिया जिसमें हम दोनों को काफी चोट आई।पूरे घटना की जानकारी दुमरियागंज पुलिस को दिया, दुमरियागंज पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

आवश्यकता है

हिन्दी दैनिक स्वतंत्र प्रभात समाचार पत्र में काम करने हेतु, इच्छुक एवं अनुभवी लोगों की आवश्यकता है।

खबरों का सच्चा साथी, स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात के ऑनलाइन चैनल को काम करने हेतु अनुभवी लोगों की आवश्यकता है।

अपना बायोडाटा भेजें

9511151254

आवाज उठाएं जुर्म के खिलाफ

www.swatantraprabhat.com

जिला एवं तहसील स्तर पर ब्यूरो चीफ, स्टिपेंड और विज्ञापन प्रतिनिधियों की आवश्यकता है। इच्छुक एवं अनुभवी व्यक्ति संपर्क करें।

